# भूमण्डलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार

**मनोरम**
शोधछात्र,
अर्थशास्त्र विभाग

**सारांश**

प्रस्तुत शोध पत्र में भूमण्डलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पर उसके प्रभाव का विश्लेषण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अनान ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0 डी0 आई0) का फायदा यह बताया कि इससे बेरोजगारी कम होगी। परंतु उपरोक्त कथन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत से कोई अच्छा बदलाव तो नहीं होगा परन्तु बेरोजगारी की दर जरूर बढ़ जाएगी।

**मुख्य शब्द :** अर्थव्यवस्था, प्रत्यक्ष, भूमण्डलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय

**प्रस्तावना**

विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, पूँजी, सेवाओं एवं तकनीकी ज्ञान के निरंतर आदान–प्रदान से परिवर्तन की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई। इससे विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ा एवं उत्पादन प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। विश्व के आर्थिक परिदृश्य से सम्बन्धित इन परिवर्तनों को ही हम भूमण्डलीकरण की संज्ञा देते हैं। भूमण्डलीकरण अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र से संबन्धित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से पूरे विश्व में भूमण्डलीकरण का तात्पर्य एक केन्द्रीय व्यवस्था से है जिसमें पूँजी राष्ट्रीय सीमाओं को लांधकर मुक्त रूप से विचरण करती है। अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम एवं सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय[4] संस्थाओं तथा अमीर देशों के दबावों से राष्ट्रों के नियम–कानून समाप्त किये जाते हैं और एक मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाकलित किया जाता हैं। इसमें दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिससे भूमण्डलीकरण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है।[1] आज अपने देश में विकास के जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उसमें बेरोजगारी कम करने की बात तो की जा रही है परन्तु भूमण्डलीकरण के लागू होने से सभी प्रयास फलीभूत नहीं हो रहे हैं। इसे हम भली–भाँति समझ सकते हैं। भूमण्डलीकरण, विदेशी पूँजी अंतर्प्रवाह एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से सम्बन्धित मिथकों में से सबसे बड़ा मिथक यह है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे एवं बेरोजगारी का संकट दूर हो जाएगा। 'अंकटाड' की विश्व निवेश रिपोर्ट 1999 की प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अनान ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0 डी0 आई0) का एक फायदा यह बताया था कि इससे बेरोजगारी कम होगी।[2]उपरोक्त मिथक की वास्तविकता तो कुछ और ही है । बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा नहीं करती। एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रोफेसर ने वहां के बड़े रिटेल की एक बड़ी समस्या के बारे में बताया। सदैव ''सबसे सस्ते विक्रेता'' की खोज के कारण अमेरिका में बड़े रिटेलर्स अब दूसरे देशों के बाजारों में पहुंच गए हैं। 'वालामार्ट' या 'टार्गेट' जैसे रिटेलर्स अमेरिका में बना माल बहुत कम रखते या बेचते हैं। उनके अधिकतर सामान अमेरिका के बाहर से आते हैं, जिससे अमेरिकी कारखाने बंद हो गए हैं एवं लाखों लोग बेरोजगार हो गए है। बड़े रिटेलर्स का कारोबार बढ़ा है, परन्तु उत्पादन क्षेत्र में गिरावट आई है। अमेरिका में 1979 में उत्पादन क्षेत्र में एक करोड़ 95 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उसके बाद उसमें निरंतर गिरावट आती गई। 2011 में यह आंकड़ा गिरकर एक करोड़ 18 लाख तक आ गया है अर्थात् 32 साल में 77 लाख रोजगार का नुकसान अर्थात् लगभग 40 हजार रोजगार प्रति वर्ष अथवा 20 हजार रोजगार प्रतिमाह की हानि। यद्यपि इसका पहला कारण नई तकनीक है, जिससे कम लोगों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इसकी दूसरी वजह है बड़ी रिटेल कंपनियां, जो दूसरे देशों या 'ऑफशोर' से व्यापारिक माल खरीदती

हैं और उत्पादन क्षेत्र को बंद हो जाने पर बाध्य करती हैं।

मई 2011 में अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर 9.1 था। वहां एक करोड़ 39 लाख लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के आंकड़े आसानी से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि रोजगार का मूलभूत संरचना को बड़े रिटेल ने बदलकर रख दिया है। सबक बिल्कुल साफ है। मल्टी–ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारी तादाद में भारतीय उत्पादों के स्थान पर विदेशी उत्पादों को ले आएगा, जिससे उत्पादन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार घटेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसर पैदा करने में अच्छी भूमिका नहीं निभा रही। नेशनल सैंपल सर्वे ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण–2009–10 में बताया है कि देश की आधी से अधिक (51 प्रतिशत) श्रमिक संख्या स्वरोजगार में हैं, 16 प्रतिशत नियमित वेतन वाली नौकरी में, जबकि 33.5 प्रतिशत श्रमिक दिहाड़ी मजदूरी में लगे हैं।[3] पिछले दस साल में, नियमित वेतन वाली नौकरी की श्रेणी में औसतन का एक लाख रोजगार प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। हमारी बढ़ती जनसंख्या के साथ इस स्तर की रोजगार वृद्धि अपर्याप्त है। रोजगार के जरिये सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भारतीय रिटेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में तकरीबन एक करोड़ 30 लाख रिटेल प्रतिष्ठान या खुदरा विक्रेता हैं। आईआरएस–2011 के अनुसार, 2 करोड़ 55 लाख लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। इनमें वे विक्रेता भी शामिल हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है।[4] देश के कुल रोजगार का 11 प्रतिशत इस क्षेत्र की बदौलत है, और इस मामले में कृषि के बाद यह दूसरे स्थान पर है। मल्टी–ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सीधा शिकार वैसे लोग ही बनेंगे, जो किसी तरह रिटेल क्षेत्र से अपना गुजार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था उन्हें रोजगार के दूसरे विकल्प नहीं दे सकती। रिटेल में रोजगार के सुरक्षा वॉल्व के बिना सामाजिक अशान्ति किसी भी हद तक जा सकती हैं। सरकार ने मल्टी–ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की जो दलीलें दी हैं, वे बनावटी हैं। एक दलील यह है कि किसानों को उनके उत्पाद पर मिलने वाली कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा अदा की गई कीमत के बीच बड़ा अन्तर है। यह अन्तर 'बिचौलियों' द्वारा हड़प लिया जाता है। ये विदेश रिटेर्लस सीधे किसानों से खरीदेंगे और 'बिचौलियों' को हटाकर वे किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत देंगे। बड़े रिटेलर भी 'बिचौलिए' हैं। उनकी व्यापारिक नीति सरल है– कम से कम दाम में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचो। दलील यह है कि जब बड़े रिटेलर किसानों से खरीदने के लिए बाजार में आएंगे, तो वे किसी तरह प्रचलित मूल्यों की अनदेखी कर किसानों को अधिक कीमत देंगे। ऐसा कतई नहीं होने वाला। इसके विपरित बड़े रिटेलर किसानों की मंडी में जाएंगे और कुछ ही समय में एकाधिकार जमाकर वहां की स्पर्द्धा को समाप्त कर देंगे। फिर किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए बड़े रिटेलर के रहमोकरम पर रहेंगे। किसानों को अच्छी कीमत मिलने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। एक, अच्छी सड़कें। दूसरी, जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के बेहतर भण्डारण की क्षमता। तीसरी, वक्त पर बाजार की सही जानकारी। सेलफोन ने इस आखिरी जरूरत को काफी हद तक पूरा कर दिया है। बाकी दो का रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कोई वास्ता नहीं। भारत में बुनियादी ढांचे की दो समस्याएं हैं– सड़क और बिजली। भारत की 30 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों में से राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग दो प्रतिशत है, राज्यों के राजमार्ग चार प्रतिशत, जबकि 94 प्रतिशत जिला और ग्रामीण सड़कें है। ग्रामीण और जिला सड़कें राज्य सरकार के विषय हैं, और यहीं पर आपूर्ति–श्रंखला संरचना ढह जाती है। इसी तरह, 1,74,000 मेगावाट की मौजूदा क्षमता के बावजूद केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण ने अगले वित्त वर्ष और उसके बाद के लिए जरूरत के मुकाबले विद्युत उत्पादन दस फिसदी कम रहने का अनुमान लगाया है। इस वजह से नियमतः बिजली जाती है, जो कोल्ड चेन के परिचालन को बेहद मुश्किल बना देती है। बड़े रिटेलर सड़क और बिजली के इस मुद्दे को नहीं सुलझा सकते। आपूर्ति श्रंखला के बुनियादी मसलों को सुलझाने और कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने की उनकी क्षमता सीमित होगी। यह भी कहा जाता है कि भारतीय औद्योगिक घराने पहले से ही खुदरा बाजार में हैं, ऐसे में विदेशी रिटेलर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस दलील से अधिक भ्रामक कुछ नहीं हो सकता। जब 'वालमार्ट' 'टेस्कोस' और 'कार्रेफोर्स' बाजार में उतरते हैं, तब वे स्थानीय स्पर्द्धा को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि उनका व्यापार उसी पर आधारित है। उनके संसाधन असीम हैं। उनके निवेश उथल–पुथल मचाने की हद तक जा सकते हैं। उनका उत्पाद स्रोत विश्वव्यापी होगा। भारतीय व्यवसाइयों ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया होगा, जो इनकी तुलना में ठहर सके। इससे समय के साथ आस–पड़ोस के किराना स्टोर्स पूरे देश में हजारों लाखों की संख्या में बंद हो जाएंगे। बाजार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, और कई परिवार तथा समुदाय आर्थिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। जहां कहीं भी ये बड़े रिटेलर गए हैं, वहां ऐसा ही हुआ है। यही वजह है कि न्यूयार्क शहर भी 'वालमार्ट' को बाहर रखने की लड़ाई लड़ रहा है।

**संदर्भ**

1. सामान्य ज्ञान दर्पण–जून 2004, पृ0 1679
2. अंकटाड की वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिर्पोट–1999
3. नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट–रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण–2009–10
4. रिर्पोट ऑफ इण्डियन रिटेल सेक्टर–2011